भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4985

01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार

4985. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संबंधी अवसंरचना का अभाव देश में ईवी को अपनाने में प्रमुख बाधा है और यदि हां, तो सरकार ने चार्जिंग अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए क्या रणनीति अपनाई है;

(ख) क्या सरकार के पास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग नेटवर्क के तीव्रतर विस्तार को समर्थन देने के लिए बजटीय आवंटन या प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना है;

(ग) सरकार ने राष्ट्रव्यापी चार्जिंग स्टेशनों के विकास और स्थापना में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने चार्जिंग प्रौद्योगिकियों और बैटरी कार्यक्षमता में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या पहल की है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव देश में इलेक्ट्रिक वाहन के अंगीकरण में एक अवरोध है। फेम-II स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 839 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना संस्थापन और प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर जोर देते हैं। व्यवसायों

के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को लाइसेंस-मुक्त कार्य बनाया गया है।

(घ) सरकार इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को निम्नलिखित तरीके से बढ़ावा दे रही हैः-

i. इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद डिजाइन तथा विकास पर किए गए व्यय को पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत पात्र निवेश का हिस्सा माने जाने की अनुमति है।

ii. भारी उद्योग मंत्रालय की पूंजीगत वस्तु स्कीम के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं) की लागत के 80% तक की सहायता प्रदान की जाती है। इन परियोजनाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) आदि जैसे प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में रखा गया है। शेष 20% का वहन उद्योग भागीदारों द्वारा किया जाता है।

*****